[Mr. Chairman.]

within a period of six months, appropriate measures for solving the problem of unemployment amongst the educated youth."

The Motion was negatived.

17.16 hrs.

RESOLUTION RE: DEVELOPMENT OF HILLY REGIONS

MR. CHAIRMAN: We now take up the next Resolution. Prof. Narain Chand Parashar.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

"This House urges upon the Government to set up a Parliamentary Committee to look into the extremely slow pace of industrial development and lack of adequate infrastructure, like, railway lines, roads, waterways, air-ways, bridges and other amenities like postal services, telecommunications, drinking water, banking and health services, institutions for technical and vocational education and the promotion of tourism, hydel-generation, forestry, agriculture including horticulture, irrigation, mass communication system in the hilly regions of the country, resulting in their extreme backwardness and to suggest ways and means to ensure their rapid economic development so as to bring them at par with the developed regions of the country within a period of five years."

माननीय सभापति जी, इस प्रस्ताव के द्वारा मैं भारतवर्ष के सभी पर्वतीय प्रान्तों, पर्वतीय क्षेत्रों, पिछड़े और गिरिजनों से भरे हुए क्षेत्रों की पीड़ा इस सदन के सामने पेश कर रहा हूं ।

हमारे देश में विकास का कार्यक्रम चला, प्रगती के चरण आगे बढ़े और आजादी से भी पहले 1938 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को प्रेरणा से श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना समिति बनी जिस में कहा गया था कि सारे देश के विकास के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रतिज्ञा करती है और उसके लिये एक योजना बनाती है ।

जब भारत आजाद हुआ तो हमारे देश के कर्णधार, भारत के पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने प्लानिंग को देश का एक इम्पार्टेन्ट आस्पेक्ट समझकर पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला जारी किया । पहली दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं बनी और योजना आयोग का गठन हुआ और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई । इसके द्वारा देश के आर्थिक विकास का ढांचा तैयार करने का जो प्रयास हुआ, उससे भारत के कोने-कोने में एक नई आशा और नये साहस का संचार हुआ ।

मुझे उन दिनों की याद आती है जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई । उस समय की बात है ग्राम-ग्राम में एक नई आशा का संचार और स्फूर्ति देखने में आया लोगों ने समझा कि हमारी किस्मत बदलने वाली है । बहुत से कार्यक्रम चले और शुरू हो गये । उस समय एक गलती हमसे हो गई कि सारे भारतवर्ष के लिये एक [illegible] गया, एक सामान्य आयोजना का आधार, जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों और आर्थिक विषमताओं को नहीं देखा गया । नताजा क्या हुआ? हरेक सैक्टर, विभाग और कार्य के लिये धनराशि मुकर्रर की जाने लगी ।

मैं मूल समस्या की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिला रहा हूं । रेलवे लाइन बननी है, पोस्ट आफिस खुलना है या कोई हवाई अड्डा बनना है या बिजली का प्रोजेक्ट बनना है, राष्ट्रीय मार्ग बनना है या कोई इंडस्ट्री लगनी है या कोई पुल बनना है, सारे देश के लिये एक अनुरूप पैटन चुन लिया गया । नतीजा यह हुआ कि प्रगति के इस मैदान में जहां पहले ही बहुलता थी, जहां पहले ही प्रगति थी, वहां तो प्रगति

और होने लगी, जो शहर थे, वह बढ़ने लगे, डाकघर बढ़ने लगे, टेलीफोनों की तादाद 10 गुना, 20 गुना और 100 गुना हो गई, मंडियां बढ़ने लगीं और बाकी देश की आबादी उस तरफ झूमने लगी । पर्वतीय क्षेत्र से ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ, वहां पर रहने वाले सारे लोग शहरों की ओर दौड़ने लगे और धीरे-धीरे पर्वतीय सम्पदा का शोषण शुरू हो गया, कच्चा माल वहां से आने लगा। पर्वतों के लोग पहले भी मजदूरी करते थे आजादी के पहले भी करते थे, बाद में भी करने लगे ।

पर्वतीय माल उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से आया और मैदानों में पहुंच गया, हिमाचल प्रदेश से आया, पंजाब के मैदानों में पहुंच गया, जम्मू-काश्मीर से आया नीचे पहुंच गया, अरुणाचल, मेघालय से आया बंगाल में पहुंच गया और इसी तरह आदिवासी क्षेत्रों से आया और बड़े-बड़े शहरों में पहुंच गया । वहां उस कच्चे माल का रूपान्तर होने लगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन गये और दुगुनी, तीगुनी कीमतों पर वापिस जाने लगे । लकड़ी आई पर्वतों से और पर्वत से आई लकड़ी जब कुर्सी बनकर पुनः वापिस जाने लगी तो उसकी कीमत 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना और 20 गुना हो गई । उसको बनाने वाला ---वही आदमी, जो वहां अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सका था---आ कर मैदान में बस गया और स्लम्ज में रहने लगा । नतीजा यह हुआ कि पर्वतीय क्षेत्रों का बड़ा भारी शोषण हुआ उसके मुकाबले में मैदानों की बहुत अधिक तरक्की हुई । मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं ।

जब भाखड़ा बांध बना, तो पंडित जी ने उसे हिन्दुस्तान की प्रगति का नमूना करार दिया । लेकिन जो भाखड़ा बांध को प्लान करने वाले थे, बनाने वाले थे, वे उसके द्वारा पैदा की गई बिजली को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पहुंचाने के लिए तो तैयार थे, उसके पानी से राजस्थान की रेतीली भूमि को सींचने के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश के गावों को बिजली देने के लिए तैयार नहीं थे । इसका नतीजा यह हुआ कि खुद भाखड़ा गांव बिना बिजली के रह गया । 1957 में मैंने गवर्नमेंट कालेज, लुधियाना की पत्रिका में एक लेख लिखा कि जिस भाखड़ा बांध से बिजली पैदा होती है और देश के दूसरे हिस्सों को रोशनी देती है, उस भाखड़ा के लोग अंधेरे में लड़खड़ाते हैं ।

भाखड़ा बांध की वजह से बिलासपुर का शहर डूब गया, लोग उजड़ गए, फासले बढ़ गए और पुल डूब गए । इसकी वजह से वहां की आबादी को उठा कर हरियाणा में हिसार और राजस्थान के क्षेत्रों में बसाना पड़ा । उन लोगों की संस्कृति खत्म हो गई। यही नहीं, बसाने वालों ने यह ध्यान रखा कि उन लोगों को एक ही जगह न बसाया जाए, ताकि उनका कोई एम. एल. ए. या मेम्बर आफ पार्लियामेंट न चुना जा सके ।

मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देना चाहता हूं लेकिन सब जगह यही तरीका अपनाया गया । पौंग डैम हो या भाखड़ा डैम, उनके विस्थापितों को जगह-जगह बिखर कर बसाया गया है और उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है । अगर इसकी जिन्दा मिसाल देखनी हो, तो राजस्थान के उस एरिया में चले जाइये, जहां उन लोगों को बसाया गया है । कहा जाता है कि उन्हें बड़ा मुआवजा दिया गया है । लेकिन संस्कृति का मूल्य क्या है ? लोगों को उनके घरों से उखाड़ कर दूसरी जगह बसा देने से ही काम नहीं चलता है । नतीजा यह हुआ है कि सारे पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वे उत्तर प्रदेश में हों, जम्मू-काश्मीर में हों, हिमाचल प्रदेश या नार्थ-ईस्ट में हों, ऐसी रूकावट पैदा हो गई है ।

जहां तक रेलवे लाइनों का सम्बन्ध है, 1956 में नंगल डैम से ऊना तक के लिए रेलवे लाइन का सरवे हुआ। आज 1981 में उसकी 25वीं जयन्ती आ गई है---उसका रजत जयन्ती वर्ष आ गया है, लेकिन आज तक उस लाइन का निर्माण नहीं हो सका है। इसका करण यह है कि योजना आयोग ने इस लाइन के लिए भी वही आधार रखा है, जो कि लुधियाना या किसी और बड़े शहर से रेलवे लाइन निकालने के लिए रखा जाता है । सरकार पहाड़ों से निकाल कर हमारी बड़ी सम्पदा को ले आई है, वह पानी को ले आई है, लेकिन जब कोई विकास-

[प्रो. नारायण चन्द पराशर]

योजना की बात होती है, तो उसके लिए सामान्य आधार लागू कर दिया जाता है, अर्थात् अगर किसी रेलवे लाइन से 10 परसेंट रिटर्न नहीं मिलता है, तो वह नहीं बनेगी, या किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए ये आयाम, डाइमेंशन्ज, और रेक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, नहीं तो वह नहीं बनेगा । सरकार ने यह तय किया हुआ है कि जिस गांव की आबादी तीन हजार है, वहां सरकारी खर्च पर टेलिफोन लगा दिया जायेगा । पहाड़ में तीन हजार की आबादी छः सात किलोमीटर के बीच में मिलेगी, लेकिन सरकार ने उसको मानने से इन्कार कर दिया है । फिर भी सरकार ने कहा कि हम वहां के रा मैटीरियल्ज के आधार पर वहीं पर कारखाने लगायेंगे । मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं । भाखड़ा के बाद नेला एक जगह है । वहां पर कर्मचन्द थापर एन्ड सन्ज ने एक कागज का कारखाना लगाने की बात की । वे लाइसेंस ले कर पांच छः साल तक बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने कारखाना लगाने से इन्कार कर दिया । मुझे अफसोस है कि जनता सरकार के शासन-काल में उन को बिना कोई सजा दिये यह इजाजत दी गई कि हांलांकि उन्होंने छः साल तक और किसी को कारखाना नहीं लगाने दिया, लेकिन अगर वे नहीं लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है । उनका कोई नुक्सान नहीं हुआ, नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश का । छः साल तक और कोई फर्म कारखाना नहीं लगा सकी। उसके बाद कोई लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ । इस तरह वहां कोई कारखाना नहीं लग सका है ।

मैं एक मिसाल और देना चाहता हूं । बिजली हिमाचल प्रदेश या जम्मू-काश्मीर या उत्तर प्रदेश के दरियाओं से पैदा हुई, लेकिन उस बिजली को पर्वतीय क्षेत्रों के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते । जोगिन्दरनगर का पावर हाउस आज भी हिमाचल प्रदेश की छाती पर खड़ा हुआ है, लेकिन उसका कब्जा पंजाब के हाथ में है, उसका प्रशासन और प्रबन्ध पंजाब के हाथ में है, और पंजाब के कर्मचारी वहां के लोगों के साथ मनमाने ढंग से जो व्यवहार करते हैं, वह एक जिन्दा मिसाल है ।

यही नहीं, एक ऐसा न्याय था, जो लोगों ने सोचा और एक ऐसा अन्याय था, जो वास्तव में हो गया । भाखड़ा बांध और पौंग डैम की झील बन गई ।

जब वहां पर उस झील के किनारे के खेतों को पानी देने की बात आई तो भाखड़ा और व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के कर्मचारियों ने उन का चालान करना शुरू कर दिया और उन के ऊपर जुर्माना करना शुरू कर दिया कि डैम का पानी भाखड़ा के बड़े-बड़े डैम्स से यहां पर रुका है इसलिए हिमाचल का इस पर कोई अधिकार नहीं है, हिमाचल वाले इस से कोई सिंचाई नहीं कर सकते। इस की सिंचाई तो बाहर जा कर होगी । मुझे खुशी है कि इस बात की कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बात को महसूस किया और बाद में इस बात की इजाजत दी । लेकिन यह तो आजकल की, पिछले साल की बात है जब कि लोगों को वहां के पानी को उठा कर अपने खेतों को सींचने की आवश्यकता महसूस हुई और उसकी इजाजत मिली । इस के पहले यह इजाजत नहीं थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था । अरुणाचल प्रदेश जो एक यूनियन टेरिटरी है, मिजोरम और इसी तरह से जम्मू और काश्मीर या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाके हैं, लद्दाख है, ये पिसते जा रहे हैं मैदानों की चक्की में । एक बड़ा भारी आर्थिक शोषण उन का हो रहा है । उस के लिए कुछ न कुछ हमें सोचना है ।

जब इस तरह की बातें होने लगीं तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने आवाज उठायी । मैं योजना मन्त्री जी का ध्यान 12 मार्च 1965 की एक घटना की ओर दिलाऊंगा । 12 मार्च 1965 को राष्ट्रीय विकास परिषद की एक पर्वतीय क्षेत्रों की समिति ने कुछ डेफिनिशन तय की कि कौन-कौन से क्षेत्र पर्वतीय हैं, उनके विकास को तेज किया जाय । अगर वह सारी रिपोर्ट पढ़ी जाय तो पता लगता है कि सारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और इस तरह के सारे क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र घोषित कर दिए गए । लेकिन पर्वतीय क्षेत्र घोषित

करने के बाद नीति नहीं बदली । वहां पर प्रोजेक्ट का रिलेन्स का एग्जाम्पशन देने की बात नहीं आई । इस तरह को बातें चलती रही । लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। मगर एक कदम आगे बढ़ा । 12 मार्च 1965 पर्वतीय प्रदेशों के लिए एक संग मील है, एक ऐसा दिन है कि जिस दिन राष्ट्र ने अनुभव किया कि हमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुछ करना है और पर्वतीय क्षेत्र कौन-से हैं उन को डिफाइन किया ।

लेकिन बाद में जैसा कि अकसर होता है, केन्द्रीय सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों की सरकारों पर डाल दी कि इन की जिम्मेदारी उन पर है । मगर संविधान में माननीय मन्त्री जी को याद होगा एक लिस्ट ऐसी है जिस को सेन्ट्रल लिस्ट कहते हैं जिस में उन विभागों की सूची है जो कि केन्द्र सरकार की ओर से चलाए जाते हैं जिस में प्रदेशीय सरकार का न तो प्रबन्ध में, न प्रशासन में और न आयोजन में कोई अधिकार है । उस के बारे में बिलकुल मौन हो गए और अभी हाल ही में हमारे एक मित्र गिरिधर गोमँगो जो उड़ीसा के हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया, प्रश्न संख्या 4941 दिनांक 25 मार्च 1981, यानी दो तीन दिन पहले, उन्होंने यह पूछा—

Districts and areas declared as hill areas in the country State-wise.

तो उस में वह जो 12 मार्च वाली सूची है उस की हत्या हो गई। उस में से बहुत से ऐसे क्षेत्र निकल गए जो सच्चे माने में पर्वतीय हैं । हिमाचल प्रदेश का नाम उस में नहीं है, जम्मू काश्मीर का नाम उस में नहीं है, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय का नाम उस में नहीं है । क्या वह इसलिए निकल गए कि वह अपने पूरे रूप में प्रान्त हैं ? तो क्या यह उन का कसूर है कि स्टेटहुड उन को मिल गई और वह स्टेट बन गए नहीं, आप देखें जवाब में यह कहा है —

The Hill Areas Development Programme is operative in 1974-75 in the following areas.

अब बात तो पूछी गई कि कौन सी हिल एरियाज आप ने रेकग्नाइज की हैं एज हिल एरियाज, तो प्लानिंग कमीशन की वह परिभाषा जिस के आधार पर इन सारे क्षेत्रों को पर्वतीय घोषित किया गया वह देना चाहिए था, उस के बजाय दे दिया जो छोटे छोटे पाकेट्स हैं, जहां पर पूरी स्टेट्स हिल स्टेट्स नहीं हैं बल्कि बड़े प्रदेशों के कुछ हिस्से जो हिली रीजन्स हैं उनकी संख्या दे दी गई । तो यह तो शायद गलती हो सकती है और मैं समझता हूं कि उस को करेक्शन भी होगी, लेकिन मैं यह कहता हूं कि हिली एरिया डेवेलपमेन्ट प्रोग्राम और प्लान में जो पर्वतीय क्षेत्र की राशि रखते हैं वह क्यों प्रदेश सरकार के स्तर पर रखते हैं ? क्यों नहीं यह रखते कि रेलवे विभाग में इतना रुपया कंट्री के हिली एरियाज के ऊपर लगेगा ।

डा. परमार ने एक बार स्टडी की और हमने एक बड़ी भारी कान्फ्रेंस यहां की थी, प्रधान मन्त्री ने उस का उद्घाटन किया था, अप्रैल 1975 की बात है, उस में एक किताब छापी थी जिसमें डा. परमार ने यह सिद्ध किया था कि सारे देश की पन्द्रह प्रतिशत आबादी और इससे भी अधिक एरिया हिली एरिया है, पर्वतीय लोग वहां रहते हैं, तो उस के लिए कुछ तो फर्ज होना चाहिए । मैं जरा माननीय मंत्री जी से यह पूछ लूं, इस का जवाब देने से पहले वह हर एक मंत्रालय से पूछें कि पर्वतीय क्षेत्रों में कितना- कितना खर्च पिछले तीस सालों में किया है ? मैंने एक मिसाल दी कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि जरा ब्राडगेज रेलवे लाइन कालका से परमाणु तक पहुंचा दीजिए क्योंकि स्टेट टैक्सेज से हमें मुक्ति मिल जाए, कालका हरियाणा में है और परमाणु हिमाचल में है लेकिन पिछले तीस सालों में डेढ़-दो किलोमीटर रेलवे लाइन भी नहीं बनी । नंगल-तलवाड़ा की लाइन कैरों साहब के वक्त से चल रही है उसका शिलान्यास भी ललित नारायण मिश्र जी ने दिसंबर 1974 में कर दिया। उन्होंने बड़ी दूर की सोची कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुछ होना चाहिए । वे गए और वहां उन्होंने कहा इस आधार को हम तोड़ देंगे । लेकिन ललित नारायण मिश्र जी चले गए और उनके साथ ही आधार तोड़ने की बात भी नहीं रही । अब वह बात मंत्री जी के हाथ में है । इसी तरह से पौंटा से जगाधरी लाइन की बात थी ।

MR. CHAIRMAN: You have already taken 15 minutes.

प्रो. नारायण चन्द्र पाराशर : मेरा कहना यह है कि आधार नहीं बदला । डिमाण्ड्स आती रही, चाहे अरुणाचल प्रदेश से, चाहे हिमाचल प्रदेश से और चाहे कश्मीर से । जम्मू-कश्मीर में जम्मू तक जरूर रेलवे लाइन बन गई लेकिन वह स्ट्रेटेजिक थी, पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी थी इसलिए बन गई लेकिन बाकी डिमाण्ड्स वैसी ही रह गई । तो अब हम क्या करें ?

पर्वतीय प्रदेशों के पास दरियाओं का पानी है । डा. परमार ने उसको फ्लोइंग गोल्ड, बहता हुआ सोना कहा था लेकिन उस को चुरा ले गए मैदानों वाले । उस पानी से बिजली निकली लेकिन उस पर भी अधिकार कर लिया मैदान वालों ने । इसमें क्या हुआ कि जब बिजली की लाइन्स आई तो टेलीफोन्स की लाइन्स तोड़ दी गई क्योंकि उससे उनमें एलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म आ जाती है । मैं आपको बताऊं कि उससे सारे बिलासपुर जिले की दूर-संचार व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो गई क्योंकि पंजाब बिजली बोर्ड बड़ी हाई पावर की ट्रांसमिशन लाइन्स ले गया जिससे हमारे सारे टेलीफोन्स बंद हो गए । अब वहां बिलासपुर के गांवों से टेलीफोन पर बात करना मुश्किल है क्योंकि गांवों में टेलीफोन लगाना असम्भव है । इस तरह से प्रगति हुई एक तरफ और प्रगति का उलटा विनाश हुआ दूसरी तरफ । इस समस्या पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया ।

अब तीसरी योजना के बजाए हम छठी योजना में आ गए हैं । 12 मार्च, 1965 की बात जो मैंने कही वह तीसरी योजना की बात है । इस बीच में तीन योजनायें चली गई, देश में कितना ही रुपया डेवलपमेंट प्लैन्स पर खर्च हो गया लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ उस रूप में कभी ध्यान नहीं दिया गया जिस रूप में वहां का आदमी उस धरती को देखता है या वहां की पीड़ा को समझता है । केवल बाहर से सरकारी फाइलों से कुछ नहीं होगा । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं डा. के. एल. राव 22 अक्तूबर 1974 को भाखड़ा गए थे । यह इस देश का एक ऐसा दिवस है जिस दिन भाखड़ा राष्ट्र को समर्पित किया गया था । मैंने वहां डा. राव से कहा कि आप बड़े अफसरों के साथ बैठकर नंगल में चाय पियेंगे और वहीं प्लान्स बन जायेंगे, आप जरा भाखड़ा गांव में भी चलें । उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारी मीटिंग भाखड़ा गांव में होगी । हमारे आफीसर्स आए, चाफ मिनिस्टर आए, हमारे राजस्व मंत्री आए, और वहां दरिया सतलुज के किनारे गोविन्दसागर के पास राव साहब की आंखों में आंसू बहने लगे कि मैं क्या देख रहा हूं, जिस भाखड़ा से सारे देश को बिजली गई है उस भाखड़ा गांव में बिजली नहीं है ? जिसभाखड़ा से लगों की प्यास बुझी है, खेती को पानी मिला है उस भाखड़ा ग्राम पंचायत एरिया में पीने का पानी नहीं है ? उन्होंने 6 लाख रुपये सैंक्शन किया और कहा कि सारे पुल जो डूब गए हैं भाखड़ा बांध बनने से वह सारे बनाए जायेंगे । लेकिन आप जानते हैं कि पर्वतों की किस्मत ऐसी है कि जब कभी उसको कोई दोस्त मिलता है तब पता नहीं उसको कोई ऐसी बात हो जाती है जैसे राव साहब ने आकर इस्तीफा दे दिया और मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हमारे पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है । इसी तरह से एल. एन. मिश्र जी ने कहा था कि रेलवे लाइन को शुरू करो परन्तु उस के बाद उनकी मृत्यु हो गई । उसके बाद जनता सरकार ने रिकार्ड खत्म कर दिया । अब हमें देखना यह है कि यह जो पीड़ा है उसको समझने का तरीका क्या है । तरीका यही है कि वहां पर अधिक खर्चा किया जाए ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा): पर्वतीय क्षेत्र के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है लेकिन अब किसी मिनिस्टर को वहां आप मत ले जाना ।

प्रो. नारायण चन्द्र पाराशर : जिन्होंने वहां पर काम किया है उनका तो प्रमोशन भी हो गया है ।

MR. CHAIRMAN: Which Minister is he inviting now?

प्रो. नारायण चन्द्र पाराशर : वहां पर मिनिस्टर के जाने या न जाने का आशय नहीं

है, आशय यह है कि आप इस आधार को बदलिए। जो क्राइटीरिया है उसको बदलिए जिससे वहां का काम बने। यह भी देखने की बात है कि लोक लेखा समिति (पांचवीं लोक सभा) में नयी रेलवे लाइनों पर एक रिपोर्ट बनाई। उस सिलसिले में यह पूछा गया था कि हर राज्य में कितनी रेलवे लाइन बनाई गई, पिछले तीस वर्ष में कितना-कितना रेल मार्ग एक राज्य में बना तो उसमें जितना पर्वतीय क्षेत्र था, जम्मू-कश्मीर तक उन सभी में जीरो दिखाया गया था। पिछले तीस वर्षों में किसी क्षेत्र में कोई रेलवे लाइन कभी नहीं बनी।

जब प्रोजैक्ट बनते हैं तो उन का पानी बाहर ले जाएं, बिजली पैदा हो तो उस गांव को न मिले। जो इण्डस्ट्री वहां लगने को हो, वह लग न सके, इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वह बन न सके, तो ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश का क्या होगा? सारे हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा करने की इतनी क्षमता है कि वह सारे उत्तर भारत को बिजली सप्लाई कर सकता है। सारे भारत की बिजली पैदा करने की 30 प्रतिशत क्षमता हिमाचल में है, लेकिन पैसा नहीं है। हमारे लिए यह शर्त लगाई जाती है। कि हरियाणा बनायेगा, पंजाब बनायेगा, थीयम-डैम बनायेंगे, सब कुछ बनेगा लेकिन उस में हिमाचल को इतना भाग भी देने को तैयार नहीं है जिस से कि सारे हिमाचल को लाभ हो सके।

आप ने वर्ल्ड बैंक के साथ बहुत सारी योजनायें ली हैं। मैंने भी वर्ल्ड बैंक के दफतर वाशिंगटन में जा कर देखा है--वहां हिमाचल के लिए कोई भी योजना वर्ल्ड बैंक नहीं बना सका। हिन्दुस्तान के किसी भी पर्वतीय क्षेत्र के लिए वर्ल्ड बैंक ने कौन सी योज्ना बनाई है यह भी मुझे मालूम नहीं है। डिरिंकिंग-वाटर प्रोजैक्ट के लिए आप एक करोड़ रुपया पंजाब को दे सकते हैं, कृपा कर हिमाचल के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था कीजिए।

इसी तरह से आप ने 6 रेलवे लाइनों उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए घोषित की है। यह खुशी की बात है लेकिन घोषित करने या स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, सवाल निर्माण का है, काम करने का सवाल है। आज एक पहाड़ी नौजवान जब यह समझता है कि उसके साथ यह अन्याय हुआ है--उस की जमीन पानी में डूब गई क्योंकि वहां उिसफ िखाष िष्ल ीिर एदढछ टद्रडाी छढ पर डैम बन गया, जो जंगल था उस को काट लिया गया, वहां पर इण्डस्ट्रीज बन गई और जो खनिज पदार्थ था उसका दोहन हो गया, एक्सप्लायटेशन होगया, एक्सट्रैक्शन हो गया जो पहाड़ी नौजवान पहले सेना में आसानी से भरती हो जाता था, अब आपने राष्ट्रीय सेना घोषित करके सारे प्रान्तों की आबादी के हिसाब से बांट दिया और यह फील्ड भी उस से छीन लिया। कहीं पर आपने राष्ट्रीय आधार बना दिया, कहीं आप ने आबादी को आधार मान लिया, लेकिन जिस आधार पर पहले हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मीजोराम, नागालैंड और आसाम तथा जम्मू-काश्मीर को फायदा होता था--मेहरबानी करके उस तरफ भी ध्यान दीजिए।

आप शिक्षा के क्षेत्र को देखिए--सारे हिमाचल में एक भी इन्जीनियरिंग कालिज नहीं है। जहां तक वोकेशन गाइडेंस की बात है--वह भी नहीं है। इरिगेशन स्कीम्ज का जहां तक सम्बन्ध है--आप को मालूम ही है कि पानी बाहर ले जायेंगे लेकिन हिमाचल में नहीं ले जायेंगे। अब उस तरफ कुछ ध्यान दिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पेय जल योजनायें या इरिगेशन की योजनायें हैं उनमें पर्वतीय क्षेत्रों का भी हिस्सा होना चाहिए जो उनके लिए फायदे मन्द हों। मैंने इसी सन्दर्भ में एक बिल पांचवीं लोक सभा में 15 नवम्बर, 1975 को पेश किया था जिस में संविधान की धारा 366 के संशोधन का सुझाव दिया था। आप इस को अमेण्ड कीजिए और उसमें एक नया उप-भाग (एफ) लगाइये। हिली एरियाज के लिए जो प्लानिंग कमीशन की परिभाषा है, वह मैंने खुद नहीं बनाई है 12 मार्च, 1965 वाली, उसके अनुसार हर विभाग में हिली एरियाज की उन्नति के लिए अलग से खर्च निर्धारित कीजिए। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अपनी इस पालिसी को देखे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो छोटी-छोटी सरकारें हैं क्या वे इतनी सक्षम

[प्रो. नारायण चन्द पराशर]

है कि सारे मामलों में स्वंय आत्म-निर्भर हो जाएगी ? मैं कहता हूं कि नहीं हो सकती है । इस लिए केन्द्रीय सरकार पर्वतीय प्रदेशों के विकास का दायित्व अपने हाथ में ले । इतने सालों से उन के साथ जो अन्याय होता रहा है उस को देख कर सुचारू रूप से उन की उन्नति के दो ही उपाय हो सकते हैं--एक तो संविधान में संशोधन कीजिए और जब इंगलैंड में स्काटलैंड के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है, फ्रांस, स्पेन और इटली में हो सकता है तो क्या वजह है कि हिमाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए नहीं हो सकता है । आप को यह काम अवश्य करना चाहिए जिस से वहां के लोगों का शोषण बन्द हो सके । दूसरे--यह कि संसदीय समिति बनाई जाए जो कि सभी दलों पर आधारित हो--चाहे उस को सरकार बनाये या माननीय अध्यक्ष जी बनायें--वह जा कर देखें कि वे कौन से कारण है जिन कारणों से पर्वतीय प्रदेश पिछड़े हुए हैं और मैदान आगे बढ़ गये हैं । लुधियाना और बड़े नगर तो आगे बढ़ गए हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश के गांव पानी में डूब गए या उजड़ गए । इस लिए मेरा माननीय सदन से यह अनुरोध है कि अब वह समय आ गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जब कुर्बानी देने की बात थी तो अकेले हिमाचल प्रदेश के 1049 जवानों ने हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा के लिये अपना खून और जानें दीं । हिन्दुस्तान का पहला परमवीर चक्र विजेता--मेजर सोमनाथ शर्मा, जिस ने जम्मू काश्मीर को बचाने के लिए 3 सितम्बर, 1947 को हवाई अड्डे पर लगातार 6 घन्टे गोलियां खाईं--वह हिमाचल का रहने वाला था, कुरबानी की बात है, वीरता की बात है तो पर्वतीय क्षेत्र सब से आगे हैं । जब डैम बनाये जाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों की छाती पर बनते हैं, जिस से कि लोग उजड़ते हैं और उनके बच्चे रोते हैं । सारे संघर्ष में पर्वतीय क्षेत्र हमेशा आप के साथ आगे रहे--चाहे स्वतंत्रता संग्राम की बात हो या कोई दूसरी कुर्बानी की बात हो, सभी दिशाओं में उन्होंने कदम से कदम मिला कर आप का साथ दिया है । इस लिए कोई वजह नहीं है कि उनके आर्थिक विकास की तरफ से आंखें मूंद ली जाएं और वही आधार फिक्स कर दिये जाएं जो दूसरे बड़े शहरों या कमर्शियल जगहों के लिए किए जाते हैं ।

मेरा सदन से अनुरोध है--इस वर्ष सारी दुनियां में डिफिकंग वाटर डिकेड लांच कर रहे हैं--यू.एन.ओ. ने इस काम को शुरू कर दिया है और यहां पर भी हम सिंचाई योजनाओं के लिए पैसा दे रहे हैं, हमारी 6ठी पंचवर्षीय योजना भी सुचारू रूप से चलने वाली है, तो पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देदें--उसके अन्दर व्याप्त निराशा को आशा में बदल दें, उनके अन्दर फैले अन्धकार को ज्योति में बदल दें, उन के लड़खड़ाते कदमों को सम्भाल लें जिस से वे भी महसूस कर सकें कि वे भी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं । उन को यह विश्वास हो सके कि जिस तिरंगे के लिए उन्होंने जान दी थी, उस के लहराने वाले केन्द्र में बैठे हैं और वे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की गारन्टी दे रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं संसदीय समिति के गठन हेतु इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता हूं ।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"This House urges upon the Government to set up a Parliamentary Committee to look into the extermely slow pace of industrial development and lack of adequate infrastructure, like railway lines roads, water-ways, air-ways, bridges and other amenities ties like postal services, telecmmunications, drinkings water, banking and health services, institutions for technical and vocational education and the promotion of tourism, hydel-generation, forestry, agriculure including horticulture, irrigation, mass communication system in the hilly regions of the country, resulting in their extreme backwardness and to suggest ways and means to ensure their rapid economic developmen so as to bring them at par with the developed regions of the country within a period of five years"

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): Sir, I beg to move:

"That in the resolution,—

(i) after "industrial development' insert—"creation of employment opportunities, utilisation of forest resources in a planned manner, recognising and encouraging their mother tongues as medium of instruction for the advancement in the field of education".

(ii) after "Economic development" insert—"and remve their prevailing economic, social and cultural exploitation" (2).

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : साहबे-सद्र, पराशर साहब ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है---मैं उसकी ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं । अभी जो बातें उन्होंने कहीं हैं वे हमारी डे-टू-डे वर्किंग के साथ, प्लानिंग के साथ, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट के साथ ताल्लुक रखती हैं। लेकिन मैं एक बुनियादी बात की तरफ माननीय प्लानिंग मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, हिली एरियाज हैं, वे आज कल हमारी सीमा भी हैं । एक जमाना था जब कहा जाता था कि हिमालय हमारा सन्तरी है, वह हमारी हिफाजत करता है, लेकिन आज वह बात नहीं रही । आज आप देखें---नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स से लेकर गुजरात तक---हमारी सीमा के इर्द-गिर्द चाइना, पाकिस्तान और अब उनके साथ अमरीका भी---चूंकि उनके जो नये राष्ट्रपति रेगन साहब आये हैं उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि वे भी उनके साथ हैं---इनका एक संगठन बन गया है और इन्होंने हम को एक घेरे में डाल रखा है । यहां एक दोस्त ने फरमाया था कि हमारे जो पड़ौसी हैं वे हम से डरते हैं, जब कि सच्चाई यह है कि इन सब ने मिल कर हम को घेरा हुआ है---मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने यह बात कैसे कह दी, शायद वे अपने पापों से डरते होंगे गुनाहों से डरते होंगे । चीन आज पाकिस्तान में हवाई अड्डे बना रहा है, समुद्री अड्डे बना रहा है, अमरीका हथियारों से पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है---ऐसी हालत में हम उस प्रेशर को फेस करने के लिए, अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं । इन पहाड़ी एरियाज को नेग्लेक्ट कर के आप मुल्क को डिफेण्ड नहीं कर सकते । आज कल हमारे इर्द-गिर्द जो गठबन्धन हो रहा है, जो तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं---हमें उन पर बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा ।

मैंने एक दिन यहां पर कहा था और आज भी प्लानिंग मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं---अगर आप इस मुल्क को सेल्फ-रिलाएंट बनाना चाहते हैं, इस मुल्क के डिफेंस को सेल्फ-रिलाएन्ट बनाना चाहते हैं, इस मुल्क की इकानामी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें इन एरियाज में रेलवेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिये। मेरा इस सिलसिले में एक जाती तजुर्बा है---आप जानते हैं जब जम्मू तक रेलवे लाइन नहीं तो पठानकोट से माल जाता था---फौज का माल जाता था, सिविल का माल जाता था, सवारियां जाती थीं---इन सब पर जो खर्चा होता था, जो व्हीकल्ज की वीअर-टीअर होती थी, जो पैट्रोल खर्च होता था, उस के मुकाबले आज यह खर्चा---बहुत कम है । इस तरह से हमको जो बचत हुई है उस को हम रेलवे को ज्यादा एक्सपैण्ड करने पर लगा दें तो इस से मुल्क की इकानमी पर असर पड़ेगा, खर्चे में बचत होगी और सब से बड़ी बात यह होगी कि पैट्रोल पर जो हमारी डिपेण्डेन्स है, वह कम होगी, उस पर खर्च होने वाला पैसा बचेगा । मैं एक बात यहां पर और कह दूं कि अब जो तेल मिलेगा वह हिमालय से मिलेगा, दूसरी किसी जगह से नहीं मिलेगा, इस पर हुकूमत ज्यादा तवज्जह नहीं दे रही है। आप अपने स्टेटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिये इस सिलसिले में आप जो खर्च कर रहे हैं वह मैदानी इलाकों पर ही खर्च कर रहे हैं--- नतीजा यह हो रहा है कि पहाड़ी इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है । वहां पर जो एग्रीकल्चर या फारेस्ट प्रोडयूस होती है उस का सही पैसा नहीं मिल रहा है इस लिये कि उनको वहां से लाने के जराय नहीं है और जो माल लोग वहां ले जाते हैं उसकी कास्ट बहुत ज्यादा आती है । पहाड़ी लोगों की समस्याएं हल करने में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं है । आज स्वतंत्र

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

भारत तरक्की कर रहा है, अगर वहां के लोगों से पूछें तो वे कहेंगे कि पहले ज्यादा सुखी थे, आज हम दुखी हैं। अगर हम पहाड़ी एरियाज की तरक्की की तरफ तवज्जह नहीं देंगे, तब तक हमारे देश की संपूर्ण उन्नति नहीं हो सकती, हमारे ऊपर उस एरिया को नेग्लेक्ट करने का चार्ज लगाया जा सकता है। एक समय था, पंडित जी के जमाने में, शास्त्री जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, जब इस ओर तवज्जह दी जाती थी, मैं समझता था कि आज भी इस ओर तवज्जह दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कमजोर वर्ग वहीं पर ज्यादा रहता है, लेकिन वही आज नेग्लेक्ट कर दिया गया है। अभी एक वक्ता ने भी कहा और मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर वहां के जंगलों को नहीं बचाया गया तो आप मैदान को भी नहीं बचा सकते हैं। आप जो वहां की उन्नति के लिए खर्च नहीं करते, उससे चौगुना आप एंटी एरोजियन एक्टीविटीज पर खर्च कर देते हैं, पराशर जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड-बैंक का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। पिछले दिनों राम लाल जी मिले, उन्होंने बताया कि यहां प्रावधान है, लेकिन एंटी एरोजियन एक्टीविटीज के लिए। वर्ल्ड बैंक के पैसा का उपयोग क्रिएटिव एक्टीविटीज के लिए होना चाहिए मगर कटाओ की रोक पर विश्व बैंक का रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम बहेंगे ही साथ-साथ नीचे के इलाके भी बह जाएंगे। इसलिए सभापति महोदय, इस ओर स्टडी करने की आवश्यकता है, तवज्जह देने की जरूरत है कि वहां पर क्या एक्टीविटीज हो सकती हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता था। 1947 से लेकर अभी तक तीन जंग मैंने देखी हैं, चीन की जंग में तो मैं नहीं गया, लेकिन 1947, 1965 और 1971 की जंगों के अंदर मैं फौजों के साथ-साथ गया हूं, मैंने वहां जाकर देखा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक बार्डर पर सिविल पापुलेशन नहीं रहेगी, तब तक वहां हमारी सेनाएं पूरी तरह से सुरक्षा नहीं कर सकती हैं। और सिविल पापुलेशन वहां पर तब तक नहीं रहेगी, जब तक उसे अपनी धरती से प्यार नहीं होगा, उसके अंदर वह भावना नहीं जागेगी कि यह उसका घर है, उसकी सुरक्षा उसे करनी है, तब तक आर्मी वहां पर डिफैंड नहीं कर सकती। इसलिए हमको वे हालत पैदा करने हैं ताकि उनको अपने घर से मोहब्बत हो। आज महंगाई इस कदर है कि वे लोग वहां पर अपना जीवन-यापन ठीक तरह से नहीं कर पाते, फिर लड़ाई के दिनों में तो उनके पास वहां से भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हमारे जितने भी योजनाएं बनाने वाले हैं, एक भी उधर का नहीं है। यदि एक भी उधर का होता तो जरूर उस क्षेत्र की उन्नति के बारे में सोचता। पूरे भारत के लिए कोई नहीं सोचता। और भी कई इलाके हैं, मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ यह इलाका नैग्लेक्टेड है। जब तक आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक आप इस देश को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बार्डर के जो लोग हैं उनकी जिंदगी जब तक काबिले फख्र नहीं बना दी जाती, तब तक आप वहां पर डिपेंड नहीं कर सकते। अगर आप इस ओर तवज्जह देंगे तो डिफेंस पर आपका एक्सपेंडीचर कम होगा और उस बचत को आप अन्य विकास कार्यों में लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पहाड़ पर रहने वाले जो सदस्य हैं, आप उनको बुलाइए, उनके साथ बात कीजिए, उनसे सुझाव लीजिए, जो सुझाव अच्छे हों उन्हें अमल में लाइए जो अच्छे नहीं हों, उन्हें छोड़ दीजिए। इसके अलावा शहरों में रहने वाले प्रोपोर्सन्स जो वर्षों तक शहरों में रहे, वे उस क्षेत्र के लिए योजना नहीं बना सकते। इस तरह की कुछ बातें मैं आपके नोटिस में लाना चाहता था। उस क्षेत्र की उन्नति न होने के बावजूद हमारी योजनाओं पर जो व्यय बढ़ रहा है पहाड़ी लोग उसके बोझ में दबे जा रहे हैं। उस व्यय को आप कम कर सकते हैं। बार्डर के लोगों पर खर्च कर उनके मन में अपने घर के प्रति प्रेम पैदा करें, हर कीमत पर हमें वहां पर उन्नति करनी है, ऐसा करके ही हम देश की रक्षा कर सकते हैं वर्ना नहीं कर सकते।

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur). Sir, it is a very important Resolution which has been moved by

Prof. Narain Chand Parashar and that is why I support this Resolution. While supporting this Resolution, I want to draw the attention of the House to the present prevailing conditions of the tribal people. There are about 41 million tribal people in our country who work out to about 745 of the total population of India. There are about 427 tribal communities and a very few of them are numerically stronger communities. Sir, about 70 per cent of the population of India are illiterate. But in the case of tribal people, more than 90 per cent of them are illiterates. This is the present position. Sir, our planners have categorised the tribal people into two groups. They are scattered all over the country with concentration in some zones. The first group of the people are those who are co-extensive with the boundaries of the State or the Union Territory and the second group of the people are hose who form part of a State. These are two groups of tribal peole who get the so-called benefits from the Centre and the States. For the first group of the tribal people the Central Government would take intiative in the matter of giving financial assistance and also would look after their welfare and for the second group of people the State Governments with the assistance of the Central Government would look after their welfare. This is the thinking of the planners. Practically the whole lot is remaining in the same darkness.

Even after 33 years of independence of our country, they are living in ab ject poverty. They are mostly illiterate, they have no shelter to live in. Most of them live in the remotest and the hilly and forest areas where a very poor development has taken place. Our planners were thinking about our tribal people and that was the reason why in the Second Five Year Plan they had included 43 experimental special multi-purpose Tribal Blocks. These were included for development in the Plan. But when the question of imlementation came, nothing appreciable was done. I would request the Government to do something real for these poor people. There is no use of working out a big proposal for these areas if it is not sincerely implemented.

Now, in the Third Five Year Plan, there was an approach through Tribal Development Blocks. These words remained in the Plan documents. Again in the Fourth Five Year Plan, it was proposed to cover 43 per cent of Tribal population under 504 tribal Deveploment Blocks. The number of the development of blocks in the Tribal areas were increased Plan after Plan. But nothing has been done in real terms. I do not know whether these blocks are blocking the development of these areas. I do not know whether the Government would say that these blocks are created to block the developmental programmes in those areas. Again in the Fifth Five Year Plan, they brought in a concept of Sub Plan for Tribal Development with adequate funds from the Centre and the States.

MR. CHAIRMAN: Mr. Mandal, are you referring to the hill area?

SHRI MUKUNDA MANDAL: Yes, Sir. The trial people are mostly living in the hill areas. Tnat is why when I talk of the tribal people, it naturally refers to the people in the hilly region.

MR. CHAIRMAN: All the people in the hilly region are not tribals.

SHRI MUKUNDA MANDAL: But mostly the tribal people are living in the hilly regions. Until and unless the hilly regions are developed, you cannot say that our country would prosper. Further, there is a constitutional responsibility on the Government to look after their development. The Constitution provides various safeguards for the protection and promotion of the interests of the scheduled tribes. Provisions contained in Articles 244(1), 244(2), 339, 275(1), 330, 332, 334, 164(1), 338, 335, 46 and the Fifth and the Sixth Schedules to the Constitution may be mentioned in this regard. The Union Government's responsibility in relation to the development of the scheduled tribes and

[Shri Mukunda Mandal]

the scheduled areas extends not only to the provision of funds for their development....

MR. CHAIRMAN: Please look to the text of the resolution; it relates to the development of hilly regions only.

SHRI MUKUNDA MANDAL: I am coming to that. You cannot develop the areas without looking to the development of the people. How can you develop a region without the development of the people. I am talking of the people. How can you ignore the conditions of people, economic and otherwise, and talk of development? As I was saying, the Union Government's responsibility in relation to the development of the scheduled tribes and the scheduled areas extends not only to the provision of funds for their development but also to evolving policies and programmes in consultation with State Governments for their development and protection from exploitation. That is my question. We may have a number of plans and programmes for the development of the hilly regions, but these will not be effective until and unless the exploitation of those people is stopped in the first instance.

It is very important that we should first understand the problems of the tribal people in the hilly regions. They are faced with acute problems like unemployment etc. Some time back, I heard the hon. Minister saying here that we should all work hard, the young generation should be disciplined and all that to ensure the progress of our nation. But the fact is that the young people are denied work; they are getting no work. In the hilly areas specially, the young people are unemployed. How can we expect the development of hilly regions when we do not look to these problems? For this the Government should come forward with concrete plans and programmes, not only go on with plans of big talks.

Further, the lanuages of the tribal people should be recognised. Until and unless you recognise their languages, you cannot develop them. Their languages should be recognised and their literature developed. That is very important.

18.00 hrs.

Sir, the landlords are exploiting them. They are not giving them remuneration. Agricultural workers are denied of their minimum wages. Village money lenders are exploiting them by lending money. Until and unless the rural exploitations are stopped, until and unless the nationalised banks come forward to help these people, until and unless the traditional village money-lending for exploitation is stopped, you cannot think of the development of the tribal areas. If the landlords, moneylenders, contractors, officials and the politicians continue to exploit them, there will be discontent and unrest among these people and they will play into the hands of the extremists.

I should also refer to Tripura. The Tripura Government has taken proper steps for the development of the tribal people and the West Bengal Government has also taken similar steps within their limited resources. But the Central Government has sufficient resources. It should come forward with concrete proposals and give financial assistance for the development of these tribal areas.

18.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*contd.*

NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT 1962 AND CENTRAL EXCISE RULES, 1944.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): Sir, the Government has decided to enhance import duty on Aluminium ingots.